भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3711
11 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन में निरंतर वृद्धि

3711. **श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः**
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के इस्पात उत्पादन में मई, 2026 के दौरान निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के कच्चे इस्पात और परिष्कृत इस्पात के उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य का योगदान कितना है;
(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र स्थित इस्पात संयंत्रों में क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और हरित इस्पात प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;
(घ) महाराष्ट्र में इस्पात इकाइयों और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को प्रदान किए गए निवेश, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और अवसंरचनात्मक सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और रोजगार सृजित करने के लिए महाराष्ट्र में नए इस्पात कलस्टर, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का विचार है; और
(च) महाराष्ट्र में इस्पात निर्माताओं के निर्यात को बढ़ाने, इनपुट लागत को कम करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (च): भारत के क्रूड स्टील उत्पादन में मई, 2026 में अप्रैल, 2026 की तुलना में 0.8% की वृद्धि हुई। महाराष्ट्र की 72 इस्पात इकाइयों ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत के क्रूड स्टील उत्पादन में लगभग 8.0-10.9% और तैयार इस्पात उत्पादन में 10.6-11.7% का योगदान दिया है। इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। नई इस्पात इकाइयों की स्थापना संबंधी निर्णय इस्पात कंपनियों

जारी..2/-

द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक दृष्टिकोणों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश भर में क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और ग्रीन स्टील प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कार्यान्वयन। जून, 2026 तक, इस योजना के तहत भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा 26,320 करोड़ रुपये का निवेश और 3.7 मिलियन टन का वृद्धिशील उत्पादन किया गया है, जिसमें 167 परियोजनाओं में से महाराष्ट्र की 33 परियोजनाएं शामिल हैं।

(ii) सरकारी परियोजनाओं में इस्पात के घरेलू स्तर पर विनिर्माण और अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति की अधिसूचना।

(iii) कम उत्सर्जन वाले इस्पात और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए ग्रीन स्टील के वर्गीकरण संबंधी अधिसूचना।

(iv) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजनाओं का अनुमोदन।

*****